20-08-2020

राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी

प्रश्न :- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(1) राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का कदम एक क्रांतिकारी सुधार है।

(2) वर्तमान में, केन्द्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसिया है।

(3) राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार केन्द्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।

(A) केवल एक (B) केवल दो

(C) केवल तीन (D) 1, 2 और 3

उत्तर :- (D) 1, 2 और 3

भूमिका :- हाल ही में 19 अगस्त, 2020 को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दी। यह एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों और सरकारी नौकरियों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा आयोजित करेगी।

परीक्षा उपयोगी बिंदु :-

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैकों और केन्द्र सरकार में गैर-राजपत्रित पदो के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) आयोजित की जाएगी। सीईटी का स्कोर तीन साल के लिए वैध है। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार उच्च स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना का कदम एक क्रांतिकारी सुधार है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एजेंसी भर्ती में आसानी और चयन में आसानी लाएगी। उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में चयनित होने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने में आसानी होगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और अन्य एजेंसियों के लिए परीक्षा आईबीपीएस, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड के माध्यम से आयोजित की जाती है।
- वर्तमान में केन्द्र सरकार में 20 से अधिक भर्ती एजेंसिया है।
- राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को पहली बार केन्द्रीय बजट 2020 में प्रस्तावित किया गया था। यह एजेंसी अधिक रूप से वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों के युवाओं के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगी। यह एजेंसी कई भाषाओं में परीक्षा आयोजित करेगी।
- केन्द्रीय बजट 2020-21 में राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के लिए 1,517 करोड़ रूपये आवंटित किए गए थे। इसे तीन साल की अवधि के लिए उपयोग किया जायेगा।

DOWNLOAD KAUTILYA ACADEMY APP FROM GOOGLE PLAY STORE
AND GET FREE DAILY CURRENT AFFAIRS

- यह फंड्स आकांक्षात्मक जिलों में स्थापित किए जाने वाले परीक्षा के बुनियादी ढांचे का हिस्सा नहीं है।

ILO-ADB की रिपोर्ट

प्रश्न :- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(1) अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक ने " Tackling COVID-19 Youth employment crisis in Asia and Pacific " पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की।

(2) भारत में तीन-चौथाई इंटर्नशिप और दो-तिहाई फर्म स्तरीय प्रशिक्षुता पूरी तरह से बाधित हो गई।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।

(A) केवल एक (B) केवल दो

(C) 1 और 2 दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर :- (C) 1 और 2 दोनों

भूमिका :- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और एशियाई विकास बैंक ने " Tackling COVID-19 Youth employment crisis in Asia and Pacific " पर एक संयुक्त रिपोर्ट तैयार की।

परीक्षा उपयोगी बिंदु :-

- यह रिपोर्ट कहती है कि COVID-19 संकट के कारण लगभग 41 लाख भारतीय युवाओं को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है।
- अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई रिपोर्ट कहती है कि नौकरी के नुकसान का बड़ा प्रतिशत खेल और निर्माण क्षेत्र से जुडे श्रमिकों को झेलना पड़ सकता है।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र के 13 देशों में लगभग 1-1.5 करोड़ युवा अपनी नौकरी खो सकते हैं।
- एशिया और प्रशांत क्षेत्र में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा नौकरियां जायेगी। इसके बाद भारत का स्थान हैं। भारत में बेरोजगारी की दर बढ़कर 32. 5 प्रतिशत हो गई हैं।
- इस क्षेत्र के सभी देशों में, श्रीलंका को 37.8 प्रतिशत की दर से अधिकतम बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है 15 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं को वयस्कों की तुलना में अधिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।
- भारत में, तीन-चौथाई इंटर्नशिप और दो-तिहाई फर्म-स्तरीय प्रशिक्षुता पूरी तरह से बाधित हो गई।

DOWNLOAD KAUTILYA ACADEMY APP FROM GOOGLE PLAY STORE
AND GET FREE DAILY CURRENT AFFAIRS

- 2019 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में बेरोजगारी 13.8 प्रतिशत थी। हर पांच युवा श्रमिकों में से चार अनौपचारिक रोजगार में लगे हुए थे। इसके अलावा, चार युवा श्रमिकों में से एक मध्यम गरीबी की स्थिति में रह रहा था।
- रिपोर्ट के अनुसार, श्रेत्र के युवा निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित होते है :

(1) कम काम के घंटे और कम कमाई के रूप में नौकरी में व्यवधान।

(2) स्वरोजगार और भुगतान वाले श्रमिकों दोनों के लिए नौकरी का नुकसान

(3) शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यवधान।

- इस रिपोर्ट में युवाओं की बेरोजगारी को कम करने में मदद करने के लिए निम्नलिखित समाधानों की सिफारिश की गई है :

(1) तत्काल और बड़े पैमाने पर लक्षित प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता होती है। इसमें मजदूरी-सब्सिडी या प्रोत्साहन शामिल हो सकते है।

(2) छात्रों की शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यवधान को कम करने के उपाय।

(3) सार्वजनिक रोजगार कार्यक्रम बढ़ाना।

मध्यप्रदेश में शासकीय नौकरी अब सिर्फ मध्यप्रदेश के बच्चों के लिए होगी

प्रश्न :- निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए :

(1) भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 धर्म, जाति, लिंग, जाति-वंश और जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव से नागरिकों की सुरक्षा करता है ।

(2) झारखंड राज्य ने स्थायी निवासियों के लिए 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा राज्य ने झारखंड के समान 75 प्रतिशत आरक्षण कोटा के साथ अध्यादेश को मंजूरी दी है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है।

(A) केवल एक (B) केवल दो

(C) 1 और 2 दोनों (D) इनमें से कोई नहीं

उत्तर :- (C) 1 और 2 दोनों

भूमिका :- हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसले में, मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के लोगों के लिए सभी राज्य सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने के अपने इरादे की घोषणा की।

परीक्षा उपयोगी बिंदु :-

- यदि ऐसा होता है, तो मध्यप्रदेश अधिवासी जनसंख्या के लिए सभी सरकारी नौकरियों के लिए सीटें आरक्षित करने वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा।

DOWNLOAD KAUTILYA ACADEMY APP FROM GOOGLE PLAY STORE
AND GET FREE DAILY CURRENT AFFAIRS

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 धर्म, जाति, लिंग, जाति के वंश, और जन्म स्थान या निवास के आधार पर रोजगार में किसी भी प्रकार के भेदभाव से नागरिकों की सुरक्षा करता हैं।
- लेकिन वही इसमें कुछ अपवाद हैं। उनमें से एक यह है कि " निवासियों" के लिए रोजगार संरक्षित किया जा सकता है।
- मध्यप्रदेश कई अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के प्रावधानों को लागू करने के लिए तत्पर है।
- झारखंड राज्य ने स्थायी निवासियों के लिए 75 प्रतिशत निजी क्षेत्र की नौकरियों के आरक्षण की घोषणा की। हरियाणा राज्य ने झारखंड के समान 75 प्रतिशत आरक्षण कोटा के साथ अध्यादेश को मंजूरी दी हैं।

KAUTILYA ACADEMY INDORE